अब 13 लाख करोड़ की परियोजनाओं के शिलान्यास की तैयारी

ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लक्ष्य में वृद्धि विभागवार तय की गई जवाबदेही, 20-30% बढ़ा लक्ष्य

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (यूपी जीआइएस) में प्राप्त निवेश प्रस्ताव को धरातल पर उतारने में जुटी राज्य सरकार ने पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी) के लिए तय लक्ष्य को बढ़ा दिया है। सितंबर-अक्टूबर में संभावित भूमि पूजन समारोह के लिए 10.05 लाख करोड़ रुपये की निवेश परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 13.06 लाख करोड़ रुपये किया गया है। विभागवार जवाबदेही तय करते हुए तय लक्ष्य में करीब 20-30 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

जीबीसी की तैयारियों में जुटी सरकार का जोर फिलहाल उन इकाइयों को धरातल पर उतारने में हैं जिनकी जमीन संबंधी दिक्कतें दूर हो गई हैं। सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वे लगातार निवेशकों से संपर्क बनाए रखें। जिन निवेशकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है या जो जवाब नहीं दे रहे है, उनके एमओयू को हटाया नहीं जाए। बता दें कि फरवरी में आयोजित यूपी जीआइएस में राज्य सरकार को 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में एक तिहाई से अधिक के निवेश को जमीन पर उतारने की तैयारी चल रही है।

जीबीसी के तय लक्ष्य में विभागवार कितना हुआ परिवर्तन

विभाग	पूर्व में लक्ष्य (करोड़ रु.में)	पुनरीक्षित लक्ष्य
सहकारिता	5,000	7,500
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	35,000	52,500
कौशल विकास	4,000	6,000
प्राविधिक शिक्षा	3,000	4,500
नोएडा	60,000	90,000
ग्रेटर नोएडा	40,000	60,000
एमएसएमई	50,000	75,000
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	10,000	12,500
आइटी एवं इलेक्ट्रानिक्स	1,00,000	1,25,000
राज्य औद्योगिक विकास प्रा.	1,60,000	2,00,000
एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विप्रा	15,000	18,750
चिकित्सा शिक्षा	7,000	8,750
पर्यटन	30,000	37,500
पशुपालन	1,000	1,250
दुग्धशाला विकास	10,000	12,500
वन	5,000	6,250
अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत	1,00,000	1,25,000
परिवहन	8,000	10,000
मत्स्य	300	375
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग	25,000	31,250
गोरखपुर औद्योगिक विप्रा	10,000	12,500
आवास एवं शहरी नियोजन	80,000	1,00,000
आबकारी	10,000	12,500
उच्च शिक्षा	50,000	62,500
नगर विकास	1,00,000	1,25,000
चीनी एवं गन्ना विकास	1,000	1,250
चिकित्सा स्वास्थ्य	10,000	12,500
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विप्रा.	35,000	43,750
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन	7,000	8,750
सूचना एवं जनसंपर्क	800	1,000
कृषि	3,000	3,750
बेसिक शिक्षा	500	625
ऊर्जा	30,000	37,500
खनिकर्म	100	125
कुल	10,05,700	13,06,375